an>

Title: Need to develop public infrastructure conducive to differently-abled people in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर देश के स्वतंत्र होने के 69 वर्षों बाद पहली बार दिव्यांगजनों की सरकार द्वारा सुध ली गई है। आज तक देश में दिव्यांगजनों के लिए जितने कायदे-कानून बने हैं, उनमें कोई न कोई खामियां अवश्य रही हैं, जिसके कारण दिव्यांगों की स्थिति और परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। यह बेहद दुखद है कि देश में दिव्यांगों की अनदेखी इतने बड़े स्तर पर की जा रही है तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए जन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, उनमें से ज्यादातर कागजी हैं। ये बात हाल ही में एक्सेसिबल इण्डिया के तहत देश में किए गए ऑडिट में खुलकर सामने आई हैं।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को विविध किस्म की वंचनाओं को झेलना पड़ता है। दिव्यांगजनों के परिवार औसत से अधिक गरीब होते हैं तथा उनके पास सम्पति के साधन भी कम होते हैं। दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी और उनके प्रति उपेक्षा भाव के चलते बहुत सारे दिव्यांग बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पाते। जो दिव्यांगजन रोजगार के अवसर पा भी जाते हैं, वे कार्य स्थलों पर रोजमर्रा की असविधाएं झेलने को मजबूर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रोत्साहन एवं दिव्यांगों के प्रति उनके गहरे सरोकार के कारण ही दिव्यांगों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने हुनर का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है।

ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के दिव्यांगजनों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे भी अपने ज्ञान व गुणों से देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे सकें।